इक्कीसवीं सदी के भारत की नई शिक्षा नीति 2020 : एक मूल्यांकन

डॉ0 उत्तरा यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर–समाजशास्त्र विभाग,
महिला कालेज, लखनऊ

शोध सारांश

वर्ष 2020 में चतुर्थ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा–प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई,2020 को मंजूरी मिली। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। 34 साल बाद ''नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'' जारी की गई है। इसरो के पूर्व चीफ के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने इसका मसौदा तैयार किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर (वर्ष 2021)शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक (त्महनसंजवत) होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गयी है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत केन्द्रित शिक्षा नीति है।नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व लक्ष्य भारत को पुनः ''एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति'' बनाना है। हम भली–भॉति जानते है कि शिक्षा नीति देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण माध्यम एवं तरीका है।

Keywords : *इक्कीसवीं सदी , भारत की नई शिक्षा नीति 2020,समृद्धि, चरित्र, राष्ट्र, इच्छा शक्ति, संवाद, क्षेत्रीय, प्रगति, समावेशी, दिव्यांग, सक्षम, समर्पित।*

भारत का अतीत अत्यंत गौरवशाली एवं समृद्ध रहा है, जो विद्या, नैतिक मूल्यों, सभ्यता–संस्कृति एवं संस्कारों से ओत–प्रोत रहा है। भारत (भारत–प्रकाश यानी विद्या में रत) समस्त विश्व को ''प्रकाश'' देने वाला (Light of World) माना जाता था। पूरी दुनियॉं में भारत वर्ष तीन बातों के लिए सुविख्यात था–1. भारत वर्ष को सोने की चिडियॉं कही जाती थी। 2.भारत को आध्यात्मिकविश्व गुरू के रूप में मान्यता प्राप्त थी और 3. भारत वर्ष को''विश्व को प्रकाश''(ज्ञान) देने वाला यानी लाइट ऑफ वर्ल्ड (Light of World) कहते थे।

1. प्राचीन एवं मध्य काल के समय भारत में कृषि–ऋषि परम्परा एवंगौ आधारित प्राकृतिक खेती प्रचलित थी। भारत मेंसमृद्ध प्राकृतिक संसाधनों यथा जमीन, जल, जंगल, जानवर (गौ) और सबसे प्रमुख जन (मानव), श्रेष्ठ जलवायु तथा कृषि ज्ञान की उपलब्धता थी। यहॉं पर पूरे वर्ष सुर्य की कृपा रहती है। कृषि–ऋषि परम्परा एवं प्राकृतिक खेती के बल पर ही भारत पूरी दुनिया का 1/3rd अन्न उत्पादन तथा एक तिहाई व्यापार करता था और भारत में प्रति हे0 125 कु0 धान–गेहॅं उत्पादन होता था। कृषि–ऋषि परम्परा, गौ आधारित प्राकृतिक खेती एवं समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण भारत को सोने की चिडियॉ कहते थें।

2. पौराणिक एवं मध्य काल में गुरू–शिष्य परम्परा, गुरूकुल शिक्षा पद्धति, व्यवाहारिक एवं प्रायोगिक कृषि शिक्षा(गुरूब्रह्मा गुरूविष्णु गुरूदेवों महेश्वरः, गुरूःसाक्षात परब्रहम् तस्मै श्री गुरवे नमः, मातृदेवोंभवः, पित्रदेवोभवः, अचार्यदेवोभवः, मित्रदेवोभवः, परस्परदेवोभवः राष्ट्रदेवोभवः, वसुधैव कुटुम्बकमदेवोभवः, दरिद्रनरायनदेवोभवः इत्यादि) के कारण भारत को विश्व गुरू कहते थें। विद्या का उद्‌देश्य है–''सा विद्या या विमुक्तये'', विद्या ददाति विनयम''।
3. आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत यथा सनातन धर्म,स्वाध्याय, आध्यात्म, योग, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता (अयम् आत्मा ब्रहम्, अहं ब्रहास्मि, कर्मण्योवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन, वासुदेव सर्वम, इशावास्यम इदम सर्वम, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म एकं सद विप्र बहुधा वदन्ति, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,)इत्यादि दर्शन को मानने के कारण भारत को विश्व का प्रकाश (Light of World) कहते थें।

उपरोक्त तीनों उपाधियों एवं उपलब्धियों का प्रमाण है– लार्ड मैकाले का भारतीय शिक्षा नीति के बारे में वक्तव्य तथा भारतीय मार्ग के बारे में ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड टायनवी का कथन :–

भारतीय शिक्षा नीति के बारे में ब्रिटिश संसद में लार्ड मैकाले ने 2 फरवरी, 1835 को दिए गए सम्बोधन में अपना शोध एवं विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि ''मैने पूरे भारत का भ्रमण किया और मैंने एक व्यक्ति नहीं देखा, जो भिखारी अथवा चोर हो। इतनी सम्पदा, इतना उच्च नैतिक मूल्य, इतनी मानसिक क्षमता, मैंने स्वयं इस देश में देखी है। मैं नहीं सोंचता कि हम इस देश को कभी भी जीत पाएंगे, जब तक कि हम इस राष्ट्र की रीढ़ ही न तोड़ दें, जो इसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। और इसलिए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि यदि हम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति (गुरू–शिष्य परम्परा, कृषि–ऋषि परम्परा) और इनकी संस्कृति को बदल दें ताकि भारतीय सोंचने लगे कि वह सब कुछ जो विदेशी और अंग्रेजी है वह अच्छा है और हमसे बेहतर है। इस प्रकार भारतीय अपना स्वमान और अपनी मौलिक संस्कृति खो देगें और वही हो जाएगें जो हम चाहते हैं– वास्तव में एक ''डोमिनियन स्टेटस अर्थात (बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य)''

भारतीय जीवन शैली एवं शिक्षा पद्धति तथा भारतीय दर्शन पर मुहर लगाते हुए बीसवीं सदी के महान ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड टायनवी कहते हैं कि ''मानव इतिहास के इस वेहद खतरनाक घड़ी में फिलहाल मानव जाति के लिए मुक्ति का एक मात्र तरीका भारतीय पथ है।''

अगर हम भारत की उपरोक्त इन तीनों समृद्ध गौरवशाली परम्पराओं को पुनः जीवन्त कर सकें तो हम अपनी प्राचीन गौरव एवं समृद्धि को पा सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य एवं उद्‌देश्य भी है।

प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का यह मॉडल (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) दुनिया के सभी शिक्षा मॉडलों यथा गुरूकुल शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी मिडियम आधारित कान्वेन्ट एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, पब्लिक एवं प्राइवेट स्कूलों के श्रेष्ठ शिक्षा मॉडलो का सम्मिश्रण है।

के0 कस्तूरीरंगन, पूर्व प्रमुख, इसरो तथा भारतीय शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि ''हमने एक ऐसी नीति निर्मित करने की कोशिश की है जो हमारी समझ में शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी, ताकि हम युवाओं को वर्तमान और भावी चुनौतियों का

सामना करने के लिए तैयार कर सकें। यह एक ऐसी यात्रा रही है जिसमें हर सदस्य ने व्यक्तिक और सामूहिक रूप से हमारे देश के व्यापक शैक्षिक परिदृश्य के विभिन्न आयामों को शामिल करने की कोशिश की है। यह नीति सभी की पहुँच, क्षमता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही जैसे मार्गदर्शी उददेश्य पर आधारित है। पूर्व–प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हमने इस क्षेत्र को एक अविछिन्न निरंतरता में देखा है और साथ ही व्यापक परिदृश्य के इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है''।

मंत्रालय का नाम परिवर्तन –मानव संसाधन को केन्द्र बिन्दु मानकर बनाया गयामानव संसाधन विकास मंत्रालय (डभ्त्व) का नाम अब पुनः शिक्षा को केन्द्र बिन्दु मानकर ''शिक्षा मंत्रालय'' रखा गया है, जबकि मेरे मत में इसका नाम ''विद्या मंत्रालय'' होना चाहिए, क्योंकि विद्या न केवल हमारी शिक्षा–संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि यह मानव विकास केन्द्रित भी है।

शिक्षा नीति का इतिहास–

- वर्ष 1948 में डा0 राधा कृष्णन की अध्यक्षता में राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ जिसकी संस्तुति पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ तथा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया।
- वर्ष 1952 में श्री लक्षमण स्वामी मुदालयार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ।
- वर्ष 1957 में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा एवं बहुउद्देशीय स्कूलों का गठन हुआ।
- वर्ष 1964 में डॉ0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इनकी मुख्य सिफारिशें थीं–1. समग्र शिक्षा पर बल 2. 10̣23 पद्धति पर बल एवं 3. कक्षा 10 के बाद विषय का चयन एवं विभाजन।
- वर्ष 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी।
- वर्ष 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीतिकी घोषणा की गयी।
- वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन हेतु आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया।
- वर्ष 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन जिसकी मुख्य सिफारिश ''बिना बोझ की शिक्षा'' थी।
- वर्ष 2005 में पुनः प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में नेशनल कूरिकूलम फ्रेमवर्क की स्थापना हुई, जिसकी मुख्य सिफारिश रटन मुक्त शिक्षा एवं बहनीय (Co-education) थी।
- वर्ष 2009 में मुफ्त शिक्षा का अधिकार (Free Right to Education) प्रदान किया गया।
- वर्ष 2020 में चतुर्थ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा–प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई,2020 को मंजूरी मिली। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। 34 साल बाद ''नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'' जारी की गई है। इसरो के पूर्व चीफ के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने इसका मसौदा तैयार किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर (वर्ष 2021)शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक (Regulator) होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने

तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गयी है।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य केन्द्र बिन्दु –

मेरे मत में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तीन मुख्य उपलब्धियों एवं विशेषताओ के अन्तर्गत समझा जा सकता हैं।क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई ख. रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा और ग.आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत यथा भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता का अध्ययन एवं आचरण। यही मूल बाते महात्मा गाँधी के बुनियादी शिक्षा (तालीम) के अंग थे।

क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई–

- प्राथमिक स्तर पर पॉचवी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
- विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया गया है।
- भारतीय संकेत भाषा (साइन लैंग्वेज) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी।
- प्राचीन भारतीय भाषाओं यथा पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- अब प्रश्न उठता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई क्यों, के संदर्भ में महापुरूषों के विचार विचारणीय है। –
- ''जिस प्रकार मॉ के दूध पर पलनेवाला बालक अधिक स्वस्थ्य एवं बलवान बनता है, उसी तरह से मातृभाषा में पढ़ने से मन और मस्तिष्क अधिक दृढ़ बनते हैं।राष्ट्रीय कार्य राष्ट्रभाषा में करने से राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ता है'' – रवीन्द्र नाथ टैगोर
- ''मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के समान है, यदि हम मातृभाषा की उन्नति नहीं कर सके और हमारा सिद्धान्त रहा कि अंग्रेजी के जरिए ही हम ऊँचे विचार प्रकट कर सकते हैं तो इसमें जरा भी शक नहीं कि हम सदा के लिए गुलाम बने।''–महात्मा गाँधी
- ''विदेशी माध्यम उलझने पैदा करती है। हमारे बच्चों के स्नायुयों पर अनुचित भार लाद दिया गया है। उन्हें रटटू और नकलची बना दिया गया है। भौतिक कार्य (शारीरिक कार्य) एवं विचार के लिए अयोग्य बना दिया गया है और अपने ज्ञान को जनता और परिवार तक पहुँचाने में असमर्थ कर दिया है। विदेशी माध्यम ने हमारी मातृ भाषाओं की उन्नति का मार्ग अवरूद्ध कर दिया है। यह एक ऐसा दोष है जिसका जड़–मूल से इलाज आवश्यक है।'' –महात्मा गाँधी
- ''अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिये दी जाने वाली शिक्षा बन्द कर दूँ और सारे शिक्षकों एवं प्रोफेसरों का यह माध्यम बदलवा दूँ। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार नहीं करूँगा। वे तो माध्यम के पीछे–पीछे अपने आप चली आएंगी।''–महात्मा गॉधी

- कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता है।
- भारत वर्ष में हिन्दी की कीमत पर अग्रेंजी एवं हिन्दुस्तान की कीमत पर अंग्रेजी और इन्डिया फल–फूल रहा है।
- पराधीन भारत में स्वतंत्र भारत के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्र एवं शिक्षित व्यक्ति थे।
- सभी विकसित देश यथा जापान, जर्मनी, चीन, फ्रांस, अमेरिका, इग्लैण्ड इत्यादि अपनी मातृभाषा के स्वाभिमान से ही विकसित हुए हैं।

ख. रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा–

श्रम की महत्ता एवं गौरव को समझाते हुए विद्यार्थियों को बचपन से ही आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना तथा स्वतंत्रकराना नयी शिक्षा नीति का उद्देश्य है। यह उद्देश्य निम्न विषयों में व्यावसायिक व प्रायोगिक शिक्षा–दीक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है।

1. कृषि एवं बागवानी 2. बढ़ईगिरी 3. लोहारी, 4. टंकरण कला 5. बुककीपिंग 6. आशु–लेखन 7. कताई–बुनाई, 8. संगीत 9. सिलाई कला 10. घरेलू अर्थशास्त्र 11. मोटर अभिंयत्रण 12. चित्रकारी, 13. किचेन गार्डेन 14. खेल–कूद, 15. नृत्य 16 स्वयं सुरक्षा मार्शल आर्ट एवं 17. योग18. पशु–पालन 19. खाद्य एवं प्रसंस्करणइत्यादि।

ग. आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत यथा भारतीय संस्कृति, दर्शन, संस्कार, सभ्यता का अध्ययन एवं आचरण–

- ''भारत वर्ष अनादि काल से 'सत्य एवं अहिंसा' की खोज आधारित धर्मो की भूमि रही है।''
- ''सत्यमेव जयते' अर्थात एक मात्र सत्य सफल होगा भारत वर्ष का राष्ट्रीय ध्येय है।
- ''अहिंसा' परमो धर्मः'' अर्थात अहिंसा सर्वोच्च सद्गुण है, में भारत का दृढ़ विश्वास है।''
- ''एकं सद विप्र बहुधा वदन्ति''अर्थात सत्य (ईश्वर) एक ही है, विद्वान लोग इसे विविध नामों से पुकारते हैं, में हमारे संतों की गहन आस्था रही है। इसलिए ईश्वर और धर्म के नाम को लेकर लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ''ईशा वास्यं इदं सर्वम्''अर्थात विद्वानों का अनुभव था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह यहां, वहां और सभी जगह है।
- ''लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु''अर्थात सभी लोक अथवा समूची दुनिया सुखी रहे उनकी प्रार्थना थी।
- ''अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।''
- ''ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।।''
- ''ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षः द्यौ शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शन्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वः द्यौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।।''–शान्ति मंत्र

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सेहम एक ऐसे सम्प्रभुता सम्पन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य का सपना देख रहे है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर आधारित हो। स्वतंत्र भारत ने

परिवहन, संचार शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति किया है लेकिन हमे मीलो आगे जाना है। भारत के पास आज तकनीकी रूप से योग्य मानव संसाधन का अकूत भण्डार है। भारत के पास आज दुनिया में सबसे बड़ी युवा शक्ति भी है। एक नये महान भारत के निर्माण में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पारदर्शी कियान्वयन से इस युवा शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है।

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संक्षेप में विशेषताएँ एवं उपलब्धियॉ –

- वर्ष 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100 : सकल नामांकन अनुपात (ळम्त्) –वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100ः सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य। सकल नामांकन अनुपात (GER) प्रदेश अथवा देश में स्कूली उम्र के कुल बच्चों और स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं।
- नवीन शिक्षा केन्द्रों की स्थापना–शिक्षा से दूर रह रहे दो करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्यधारा में शामिल करने की योजना है। स्कूल के बुनियादी ढाँचे का विकास और नवीन शिक्षा केन्द्रों की स्थापना पर जोर दिया गया है।
- स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव–स्कूल पाठ्यक्रम के 10़2 ढाँचे की जगह 5़3़3़4 का नया पाठ्यक्रम ढाँचा लागू करने का प्राविधान है। यह ढाँचा क्रमशः
- ़5 चरण– 3.8 वर्ष के बीच में तीसरे वर्ष से प्रारम्भ होकर प्रथम–द्वितीय–तृतीय वर्ष आगनबाड़ी में तथा कक्षा 1 एवं 2 तक की पढ़ाई होगी।
- ़3 चरण– 8.11 वर्षके बीच कक्षा 3, 4 एवं 5 तक की पढ़ाई होगी।
- ़3 चरण– 11.14वर्ष के बीच कक्षा 6, 7 एवं8 तक की पढ़ाई होगी।
- ़4 चरण– 14–18 वर्ष के बीच कक्षा 9, 10, 11 एवं12 तक की पढ़ाई होगी।
- 5़3़3़4का नया पाठ्यक्रम ढाचा समझने के लिए इसे हम चार भागों में बॅाट कर समझ देख सकते हैं :–
- नर्सरी ़5स्टेज :–
- 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे कवर होगें।
- पहले तीन वर्ष के बच्चे आंगनवाडी एवं प्री–स्कूलिंग शिक्षा लेंगे।
- अगले 2 वर्ष स्कूल में कक्षा 1 व 2 में पढ़ेंगे।
- प्रीपेटरी ़3स्टेज :–
- 8 से 11 वर्ष तक के बच्चे कवर है।
- कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा लेंगे।
- मिडिल ़3स्टेज :–
- 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे कवर किए जा रहे है।
- कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा लेंगे।
- सेकेण्डरी ़4 स्टेज :–
- 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे कवर होगें।
- कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा लेंगे।
- आसान होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाऍः–

- परीक्षाऍं दो बार कराने तथा वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक दो भागों मे आयोजित करने का सुझाव है।
- विद्यार्थियों द्वारा रटे हुए सवालों पर बोर्डपरीक्षा का दारोमदार अब नहीं रहेगा।
- वार्षिक, सेमेस्टर और मॉडयूलर बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पर जोर दिया गया है।
- शिक्षा स्नातक (B.Ed)कोर्स :–
- जो विद्यार्थी 12वीं के बाद शिक्षा स्नातक (B.Ed)करना चाहते हैं वे 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड (B.Ed)कोर्स कर सकते हैं।
- स्नातक के बाद दो वर्ष का (B.Ed)जबकि परा–स्नातक उम्मीदवारों के लिए 1 वर्ष का (B.Ed)कोर्स होगा।
- M.Phil की समाप्ति :–
- 4 साल का डिग्री प्रोग्प्रम, फिर M.A.और उसके बाद बिना M.Philके सीधा Ph.Dकर सकते हैं।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढॉचाः–
- एनसीईआरटी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढॉचा विकसित करने पर बल दिया गया है।
- बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना :–
- वर्ष 2025 तक तीसरी कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन–कला में सुधारः–
- 21 वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल दिया गया है।
- विद्यार्थियों को पंसदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे।
- कला एवं विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं है।
- इस नीति में कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालय का विस्तर 12 वीं तक करने का सुझाव दिया गया है।
- समान और समावेशी शिक्षाः–
- समाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों को अवसर उपलब्ध करवाने पर बल प्रदान किया गया है।
- बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक–बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना का प्रावधान है।
- दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा।
- प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और स्कूल प्रशासन :–
- शिक्षक भर्ती–प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं द्वारा किया जायेगा।
- पदोन्नति–कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर किया जायेगा।
- बुनियादी ढॉंचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों एवं प्रोंफेशनल शिक्षक समुदाय की उपलब्धता पर जोर दिया गया है।

- State School Standar के Authority"S.S.S.A." के गठन का प्रावधान है।
- उच्चतर शिक्षाः—
- वर्ष 2018 के 26.3% के सकल नामांकन अनुपात(GER) को बढ़ाकर 2035 तक 50%करने का लक्ष्य (व्यावसायिक शिक्षा सहित) रखा गया है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
- स्नातक ;न्दकमत ळतंकनंजमद्धशिक्षा के कोर्स को 3 वर्ष से 4 वर्ष करने का प्रावधान :—
- 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट प्रमाण—पत्र दिये जाने का प्राविधान है।
- 2 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने पर डिप्लोमा दिया जायेगा।
- 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी।
- 4 वर्ष की बाद शोध के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (भ्म्ब्) का गठन (चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर) किया जाएगा।
- महाविद्यालयों की संबद्धता अगले 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जाएगी तथा महाविद्यालयों को क्रमिक स्वायत्ता प्रदान करने हेतु एक तंत्र विकसित किया जाएगा।
- शोध को बढ़ावा देने हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (छण्त्थ्) की स्थापना की जाएगी।
- ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा :—
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई—शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी।
- प्रौढ़ शिक्षा :—
- वर्ष 2030 तक 100ः युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति का लक्ष्य
- शिक्षा क्षेत्र में GDPdk 6% तक निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वर्तमान में यह निवेशळक्च का मात्र2.70ः है।
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा :—
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनेगा। इससे शिक्षण—प्रशिक्षण के साथ अध्ययन् व आकलन में तकनीक अहम हिस्सा बनेगी।
- क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन् के लिए ई—सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समस्या एवं चुनौतियॉ :—

- शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों संशोधन कर कानून बना सकते हैं। इसी प्रकार कृषि शिक्षा राज्य का विषय है। इसलिए नयी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएँ आयेंगी। इसका समाधान संवाद एवं चर्चा तथा सहमति से निकाला जा सकता है।
- त्रिभाषा सूत्र में दो भारतीय भाषाएँ (क्षेत्रीय एवं अंग्रेजी) होने से संस्कृत एवं राजभाषा

हिन्दी उपेक्षित होगा। इसलिए इस विषय पर व्यापक चर्चा तथा सहमति उपरान्त ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

- अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को त्रिभाषा फारमूला को स्वीकार करने में कठिनाई होगी। विशेष रूप से बहुभाषी केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली इत्यादि में स्थानान्तरण के उपरान्त नये स्कूलों में भाषा चयन एवं प्रवेश की समस्या होगी। यह बिन्दु विचारणीय है।

- भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं, फिर भी हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा अभी भी उपेक्षित है। हम आई0आई0टी0 एवं आई0आई0एम0 और उच्च शिक्षा पर स्कूलों एवं प्राथमिक शिक्षा के मुकाबले ज्यादा खर्च करते है, जबकि यह (प्राथमिक शिक्षा) अकेले राष्ट्र–निर्माण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है इसलिए प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में जी0डी0पी0 का 6% बजट का प्राविधान किया गया है। यह स्वागत योग्य है, लेकिन अब तक शिक्षा पर जी0डी0पी0 का औसत व्यय मात्र 2.7% रहा है। भ्रष्टाचार एवं कालाधन खत्म करके बजट की व्यवस्था की जा सकती है। इस कार्य में मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों एवं गुरूद्वारों में संग्रहित अकूत सम्पत्ति का सहयोग लिया जा सकता है।

- पूर्व की दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ (क्रमशः वर्ष 1968 और वर्ष 1986) जब अपना लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पायी हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल होने की संभावनाएँ कितनी है? यह विचारणीय बिन्दु हैं। इसके लिए सभी सम्बन्धित को संवेदित, उत्प्रेरित एवं उर्जान्वित करने की आवश्यकता हैं।

- भारत में धन एवं संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास उत्तरदायीनागरिकता, राष्ट्रीय चरित्र एवं राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान एवं जर्मनी पूरी तरह से नष्ट हो गये थें। भारत की तुलना में उनके पास बहुत कम भूमि एवं अन्य संसाधन हैं, लेकिन जीवन जीने के मानकों और विकास के अन्य पहलुओं की दृष्टि से ये दोनों ही देश उत्तरदायी नागरिकता, राष्ट्रीय चरित्र एवं राजनैतिक इच्छाशक्ति के बल पर भारत से कहीं आगे है।

- गंभीरता से विचार करने पर हम पाते हैं कि आज हमारे देश के सामने असली संकट आर्थिक एवं राजनैतिक नहीं हैं, बल्कि नैतिक एवं आध्यात्मिक है। राष्ट्र को एक जीवित शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए, भारत का नैतिक एवं आध्यात्मिक पुनरोत्थान एक ऐतिहासिक जरूरत है। यह केवल राजनैतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक मिशन भी होना चाहिए। भारत एक बहुधर्मी राष्ट्र है। बहुधार्मिक भारत के सन्दर्भ में, इस राष्ट्र–निर्माण मिशन को अन्तर–धार्मिक सहयोग और संयुक्त प्रयास के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है।

उपसंहार

निश्चित तौर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020एक सराहनीय प्रयास है, जिसका हरहाल में स्वागत किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 भारत केन्द्रित शिक्षा नीति है। भारतीय

 ISSN: 2349-1876 (Print) | ISSN : 2454-1826 (Online)

संस्कृति, इतिहास और नैतिकता इसकी पृष्ठभूमि में है। यह नए युग की शिक्षा का नवसूत्र है। यह शिक्षा नीति बेहद लचीली, संवेदनशील एवं न्याय सम्मत है। यह नीति वंचित और संपन्न, शासकीय और प्राइवेट सभी के लिए एक समान है। इसमें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को महत्व दिया गया है। इसमें करीकुलर एवं एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों को समायोजित कर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की बात कही गई है। मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम बनाये जाने पर ध्यान दिया गया है। साइंस वाला विद्यार्थी कॉमर्स भी पढ़ सकता है और चाहे तो अन्य कला संगीत भी अपनी रूचि के अनुसार ले सकता है। इसके लिए शिक्षकों का योग्य होना भी आवश्यक है। इस शिक्षा से शिक्षित विद्यार्थी मल्टीडिसिप्लिनरी व्यक्तित्व का धनी होगा। योग्य शिक्षक जबतक नहीं आऍगे तबतक योग्य विद्यार्थी कैसे निकलेंगे। नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन का काम आदर्श शिक्षक का निर्माण है। जब विद्यालय चलाने में शिक्षक की भागीदारी होगी जब पढ़ाने वाला शिक्षक यह सोचेगा कि मुझे भी अपने विद्यालय का विकास करना चाहिए तथा विद्यार्थी यह सोचें कि विद्यालय के विकास में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए ? तब भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आशातीत सुधार एवं आमूलचूल परिर्वतन होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने आसपास की समस्याओं को चिन्हित करें, फिर उनके समाधान के लिए शोध करे। समस्या के समाधान के लिए शोध हो तभी उसका महत्व है। आप जितना शोध और नवाचार को महत्व देंगे उतना ही विकास होगा, चाहें किसी भी विषय का छात्र हो उसका विचार भारत केन्द्रित होना चाहिए। जब हम भारत केन्द्रित शिक्षा की बात करते हैं तो पहले हमें भारत को समझना होगा। भारत को समझने के लिए पाश्चात्य दर्शन के सापेक्ष भारतीय दर्शन को ठीक से समझना एवं अपनाना होगा। वर्षों बाद पहली बार ठीक वैसी शिक्षा नीति बनी है जैसी भारत के लिए बननी चाहिए थी।

आज अन्य देशों के लोग भी हमारी शिक्षानीति का अध्ययन कर रहे हैं। यह नीति सभी वर्ग के छात्रों के लिए ग्राह्य हैं। हमे प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे नीव मजबूत होगी जिस पर एक नये महान भारत की इमारत खड़ी की जा सकें। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020जारी होने के बाद भारत को लेकरदुनिया का नजरिया सकारात्मक रूप से काफी बदला है, जिसका अनुमान विदेशी छात्रों के भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर बढ़े रुझान से लगाया जा सकता है। विदेशी छात्रोंकीसंख्या में पिछले सालों के मुकाबले इस साल करीब 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। यह स्थिति तब है जब विश्व व्यापी कोरोना संक्रमण के प्रभाव से देश अभी भी पूरी तरह से उबरा नहीं है। आने वाले सालों में विदेशी छात्रों के भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में और बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया जा रहा है।भारतीय उच्च संस्थानों की ओर विदेशी छात्रों के इस बढ़े रुझान सेमानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) उत्साहित है। इस बढ़े रुझान को देखते हुए दुनिया के बारह और देशों में अभियान चलाने की फैसला लिया जा रहा है। वैसे तो भारत में पढ़ाई के लिए किसी भी देश के छात्र आ सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय का फोकस अभी सिर्फ तीस देशों को लेकर ही था, इनमें ज्यादातर अफ्रीकी, खाड़ी और एशियाई देश शामिल हैं।फिलहाल इस मुहिम में जो बारह नए देशों को शामिल किया गया है, वे खाड़ी और एशिया से हैं। इनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मॉरीशस व बहरीन आदि देश शामिल हैं। अब तक इन देशों के छात्रों की संख्या कम रहती थी, जो इस बार बढ़ी है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मौजूदा समय में भारत में उच्च शिक्षा के लिए 70 से ज्यादा देशों के छात्र आते हैं। शिक्षा

मंत्रालय को इसके भी दायरे को बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए ताकि आने वाले सालों में भारत में पढ़ाई के लिए सौ से भी ज्यादा देशों के छात्र आ सके हैं। कोरोना का प्रभाव कम होते ही मंत्रालय को वह फोकस वाले सभी देशों में भारतीय संस्थानों और यहां पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए प्रषिक्षण, रोड शो, सेमिनार जैसे आयोजन करने चाहिए। इस तरह से नई षिक्षा नीति 2020 माहत्मा गांधी की बुनियादी तालीम की प्रतिकृति है।

एक नये महान भारत के निर्माण के लिए भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ संवाद एवं समन्यवय के साथ मिलजुल कर वर्ष 2022 तक नई शिक्षा नीति को अवश्य ही लागू करना चाहिए ताकि भारत एक बार पुनः वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सके तथा महात्मा गांधी के सपनों का भारत निर्मित हो सके। ''मनुष्य की अन्तनिर्हित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।''– स्वामी विवेकानन्द–''ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है।''– महात्मा गाँधी–महान सामाजिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन जे0 कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कहा है कि ''आपको सिर्फ उपाधियाँ मात्र देना नहीं, अपितु हम मनुष्यों में विचारशीलता की ज्योति जाग्रत करना है ताकि हमें सवेंदनशील, सजग, सावधान और दयालु बन सकें।''जिसने ज्ञान को अपने आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को मूर्तिमान कर लिया।''– आचार्य विनोबा भावे–''शिक्षा हमारे समाज की कभी न खत्म होने वाली आत्मा है जोकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है।''– बापू–''शिक्षा की जड़ें कड़वी है, लेकिन फल मीठा है।''–

सन्दर्भ

1. यह लेख भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रकाशित विभिन्न लेखों के आधार पर तैयार किया गया है।